

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 743

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना के तहत उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना

743. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2023-24 से दी गई अनुदानों के संदर्भ में, उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम योजना के अंतर्गत की गई प्रगति का राज्य-वार ब्यौपरा क्या है
- (ख) जनवरी 2025 तक राज्यों को संवितरित किए गए अनुदानों की कुल मात्रा क्या है;
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश राज्य ने पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौपरा क्या है
- (घ) क्या रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत कोई विशिष्ट घटक है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौपरा क्या है और
- (ड.) क्या योजना का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि किसानों को वैकल्पिक और जैविक उर्वरकों की सुविधा मिलेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौपरा क्या है

उत्तर

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (ड.): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करना है।

स्कीनम के तहत पिछले तीन वर्षों के अंतराल में औसत खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त प्रोत्साहन राज्य द्वारा बचाई गई सब्सिडी के 50% के बराबर है। इन प्रोत्साहनों का उपयोग कृषि अवसंरचना से संबंधित प्रचारात्मक गतिविधियों (आईईसी) और अनुसंधान एवं विकास तथा उपज में वृद्धि के लिए किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए उर्वरकों का औसत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) 104.21 एलएमटी था। वर्ष 2023-24 के लिए, पीओएस बिक्री 105.28 एलएमटी रही, जो पिछले तीन वित्तीय वर्ष की औसत बिक्री की तुलना में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) में 1.07 एलएमटी की वृद्धि को दर्शाती है।